

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 13 Dec , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था	अक्टूबर में नए उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति 5.5% पर आ गई
Page 04 Syllabus : GS 3 : आपदा और आपदा प्रबंधन	लोकसभा ने 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया
Page 07 Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी	बीमारी एक्स क्या है और दुनिया को इसके लिए क्यों तैयार रहना चाहिए
Page 10 Syllabus : GS 3 : पर्यावरण	वायु प्रदूषण के खिलाफ बीजिंग का युद्ध
समाचार में	विलो चिप
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2: भारतीय राजनीति	शहरी स्थानीय सरकार के चुनावों पर गायब स्पोर्टलाइट

भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में थोड़ी नरमी आई है, जो अक्टूबर में 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.2% से घटकर नवंबर 2024 में 5.5% हो गई है। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण है, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी उच्च बनी हुई है। यह खबर बढ़ते आर्थिक दबावों, विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं पर, और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति समायोजन के बारे में चल रही चर्चाओं को भी उजागर करती है।

Retail inflation moderates to 5.5% in November after new high in October

Vikas Dhoot

NEW DELHI

India's retail inflation cooled slightly to 5.5% in November from a 14-month high of 6.2% in October, but remained significantly elevated for rural consumers at 5.95%, while dropping to 4.8% for their urban counterparts.

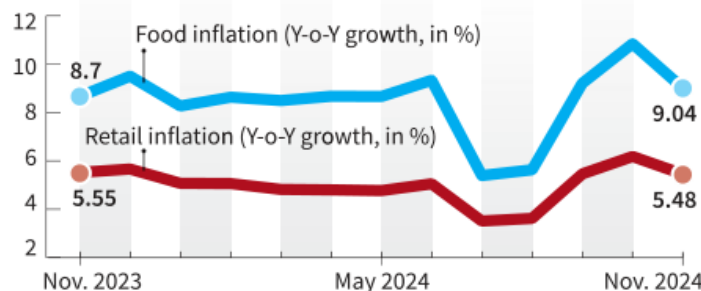
Food inflation, which has been a bugbear for hopes of an interest rate cut, also eased a tad from October's 15-month peak of 10.9% to 9.04% in November. Rural consumers experienced a slightly higher uptick of 9.1% while urban consumers saw an 8.74% gain in prices.

Vegetable prices ease

This marks the third straight month of food inflation staying above the

A mild respite

For the third straight month, food prices surged by over 9%, and consumer inflation stayed closer to 5.5%



SOURCE: MOSPI

9% mark, and overall consumer price rise of over 5%.

Vegetables inflation eased from a 57-month high of 42.2% in October to 29.33%. However, oils and fats inflation shot up 13.3%, the highest pace in two and a half years, and significantly over the 9.5% rise in the previous month and

the mere 2.5% inflation in September.

"The decline in inflation in November 2024 is mainly due to decline in inflation in 'food & beverages' group," the National Statistics Office (NSO) said, pointing to a significant drop in price rise observed in vegetables, pulses, sugar, fruits, eggs, milk, spic-

es, transport, communication, and personal care and effects. But these moderations were only marginal in some cases.

Fruits inflation eased only marginally from 8.4% in October to 7.7% in November. Pulses inflation dropped to 5.4%, the lowest in at least two years, and cereals inflation stood at 6.9%.

Six of the 22 States (including the erstwhile State of Jammu and Kashmir), for which the NSO calculates monthly inflation rates, observed a price rise of over 6% – the upper limit of the Central bank's inflation target – in November. These included Chhattisgarh (8.4%), Bihar (7.55%), Odisha (6.8%), Uttar Pradesh (6.6%), Kerala (6.3%), and Madhya Pradesh (6.05%).

खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण मुद्रास्फीति में कमी

- खाद्य पदार्थों की कीमतों के रुझान: समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में कुछ राहत मिली, सब्जियों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी (42.2% से घटकर 30% रह गई) और खाद्यान्नों की कीमतों में 28 महीनों में सबसे धीमी गति से वृद्धि हुई।
- दालें और तेल की कीमतें: उच्च मुद्रास्फीति की लंबी अवधि के बाद दालों की कीमतों में 5% से कुछ अधिक की गिरावट देखी गई, लेकिन खाद्य तेल की कीमतों में 13.3% की तीव्र वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक मूल्य वृद्धि और घरेलू नीति परिवर्तनों के कारण हुई।

► ग्रामीण मुद्रास्फीति प्रभाव: कुछ खाद्य पदार्थों में कुछ राहत के

बावजूद, ग्रामीण उपभोक्ताओं को लगभग 6% मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा, जिसमें उच्च खाद्य कीमतों ने शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में उनकी क्रय शक्ति को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया।

विनिर्माण और सेवाओं पर मुद्रास्फीति का प्रभाव

- व्यवसायों पर लागत दबाव: विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों ने लागत दबाव में वृद्धि की सूचना दी, जिससे फर्मों को 12 वर्षों में सबसे अधिक गति से कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- मुद्रास्फीति पर सरकार की प्रतिक्रिया: जबकि सरकार का मानना है कि खाद्य मूल्य अस्थिरता को मौद्रिक नीति निर्धारित नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के व्यापक प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है।
- RBI के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान पर प्रभाव: RBI ने अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4.8% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया, जिससे उम्मीद है कि मुद्रास्फीति 2025 के मध्य तक 4% के अपने लक्ष्य से ऊपर रहेगी।

ब्याज दर में कटौती और राजकोषीय उपायों पर बहस

- ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें: फरवरी की RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं, हालांकि नवीनतम डेटा से पता चलता है कि मुद्रास्फीति और कम हो सकती है और विकास थोड़ा बढ़ सकता है, जिससे इस तरह के कदम की आवश्यकता कम हो जाती है।
- राजकोषीय विवेक और विकास समर्थन: सरकार को उम्मीद हो सकती है कि 2025-26 के लिए उसका बजट, जिसे फरवरी की MPC बैठक से पहले पेश किया जाएगा, राजकोषीय अनुशासन का प्रदर्शन करेगा और जीवन-यापन की लागत को कम करने के उपायों का प्रस्ताव करेगा, जिससे दरों में कटौती का मामला मजबूत होगा।
- मौद्रिक नीति पर विचार-विमर्श: ब्याज दरों में कटौती के दबाव के बावजूद, आरबीआई का सतर्क रुख यह संकेत देता है कि कोई भी निर्णय आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के रुझानों के बारे में चिंताओं के साथ संतुलित होगा, जिनके आने वाले महीनों में कम होने की उम्मीद है।

UPSC Mains practice Question

प्रश्न: भारत में मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का आकलन करें। इन प्रवृत्तियों के मद्देनजर भारतीय रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति समायोजन के लिए किस तरह का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? (150 words/10m)

➡ विधेयक का उद्देश्य संस्थागत सुधारों को शुरू करके और विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर भूमिकाओं को स्पष्ट करके पूरे भारत में आपदा तैयारी और प्रबंधन को बढ़ाना है।

Lok Sabha passes Bill to amend the Disaster Management Act of 2005

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Lok Sabha on Thursday passed a Bill to strengthen the working of national and State disaster management authorities, with the Centre stressing that the legislation will help State governments deal with disasters better.

The House cleared the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 by a voice vote. Several amendments moved by the Opposition members were negated.

Pointing out that State governments had flagged several difficulties in implementing the Disaster Management Act of 2005, Union Minister Nityanand Rai said the new Bill would not only overcome them but also strengthen the disaster management system. The Bill seeks to bring clarity and convergence among stakeholders working in the field of disaster management.

"When a disaster hits, it hits the country as a



The new Bill seeks to bring clarity and convergence among stakeholders in the field of disaster management. THULASI KAKKAT

whole; this Bill will prepare the country to handle disasters better," he said.

Many Opposition members, however, said that the Disaster Management (Amendment) Bill, 2024 only talks about creation of a plethora of organisations. Saugata Roy of the Trinamool Congress alleged that the Modi government was not able to manage the pandemic properly and a large number of people died.

He said, "This Bill creates a plethora of organisations and has added a number of English terms".

Captain Viriato Fernandes of the Congress

said that while the members were talking about following a holistic approach to deal with disasters, the Bill seemed to have gone against that approach.

Another Congress member, G.K. Padavi, pointed out that climate change had not been included in the Bill and the word "compensation" had been replaced with "relief". "It (promotes) over centralisation," Mr. Padavi said.

Taking a dig at the Opposition, BJP member Arun Govil said disruptions in Parliament on a daily basis was a man-made disaster as it hurt Parliament's dignity.

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान:

➡ आपदा प्रबंधन को परिभाषित करता है:

- आपदा प्रबंधन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण शामिल है - व्यवस्थित प्रयास के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने का अभ्यास।
- इसके माध्यम से आपदा के कारणात्मक तथ्यों का विश्लेषण और प्रबंधन किया जाता है -
 - खतरे के प्रति जोखिम को कम करना;
 - लोगों, संपत्ति, बुनियादी ढांचे, आर्थिक गतिविधि, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की कम भेद्यता; और
 - प्रतिकूल घटनाओं के प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए बेहतर तैयारी, लचीलापन और क्षमता।

○ **राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस: डेटाबेस में शामिल होंगे -**

- आपदा मूल्यांकन,
 - निधि आवंटन विवरण,
 - व्यय,
 - तैयारी और शमन योजना,
 - जोखिम के प्रकार और गंभीरता के अनुसार जोखिम रजिस्टर, आदि।
- **यूडीएमए का गठन:** विधेयक में दिल्ली और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) का प्रावधान है।
 - **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ):** यह राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ के गठन का प्रावधान करता है।
 - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को सशक्त बनाता है:** देश में आपदा जोखिमों की पूरी श्रृंखला का समय-समय पर जायजा लेना, जिसमें उभरते आपदा जोखिम भी शामिल हैं।
 - **एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) को सशक्त बनाता है:** राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियों द्वारा पहले बनाई गई योजनाओं के बजाय क्रमशः राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करना।
 - **कुछ संगठनों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है:** विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च-स्तरीय समिति जैसे कुछ पूर्व-अधिनियम संगठनों को वैधानिक दर्जा भी प्रदान करता है।
 - **केंद्र और राज्य सरकारों को सशक्त बनाता है:** किसी व्यक्ति को आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कोई कार्रवाई करने या कोई कार्रवाई करने से परहेज करने का निर्देश देना और ₹10,000 से अधिक का जुर्माना लगाना।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 का औचित्य/महत्व:

- 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशें: विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करने की आवश्यकता थी।
- अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाता है: आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और समितियों की भूमिकाओं में। यह हाल ही में वायनाड त्रासदी के संदर्भ में प्रासंगिक है।
- एक परिवर्तनकारी कदम: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए राष्ट्र की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में।
- **एक व्यापक, केंद्रीकृत आपदा डेटाबेस:**
 - राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर आपदाओं के लिए तैयार होने, उनका जवाब देने और उनसे उबरने की उनकी क्षमता में सुधार करके महत्वपूर्ण रूप से लचीले समुदायों का निर्माण करेगा।
 - यह अधिक कुशल संसाधन आवंटन, हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और संकटों के दौरान समय पर, सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 की विपक्ष की आलोचना:

- **संघवाद पर चिंताएँ:** विधेयक राज्यों के अधिकारों को कमजोर करता है और आपदा प्रबंधन को राज्य से केंद्रीय विषय में स्थानांतरित करता है। यह विधेयक संविधान में निहित सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
- **न्यायसंगत अधिकार के रूप में राहत:** कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार के रूप में आपदा राहत की अनुपस्थिति का हवाला चक्रवात मिचांग के बाद तमिलनाडु द्वारा सहायता प्राप्त करने के संघर्ष से दिया जाता है।
- **नौकरशाही ओवरलैप:** एनडीएमए के माध्यम से केंद्र को दी गई व्यापक शक्तियाँ और कई प्राधिकरणों के गठन के परिणामस्वरूप नौकरशाही संघर्ष की संभावना हो सकती है।
- **सरकार का स्पष्टीकरण:** विधेयक को समवर्ती सूची में प्रविष्टि 23 ("सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजित बेरोजगारी") के तहत पेश किया जा रहा था और यह विधेयक 2013 में एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद आया था।

निष्कर्ष:

➡ "आपदा किसी एक पार्टी, व्यक्ति या क्षेत्र के लिए नहीं होती - यह पूरे

देश को प्रभावित करती है।"

- ➡ आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024, भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में बहुत जरूरी बदलाव प्रस्तुत करता है।
- ➡ जैसे-जैसे प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ती जा रही हैं, इस कानून की सफलता इसके कार्यान्वयन और केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी सहयोग पर निर्भर करेगी।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करें और चर्चा करें कि वे आपदाओं के प्रति भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया को कैसे बढ़ाते हैं। (250 Words /15 marks)



कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में रिपोर्ट किए गए इस प्रकोप ने, जिसने अब तक 400 से अधिक लोगों की जान ले ली है और जिसे अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है, चिंताएं पैदा कर दी हैं कि यह रोग एक्स का एक उदाहरण हो सकता है।

What is Disease X and why the world should prepare for it

COVID-19 is regarded as the first instance of a real Disease X. When SARS-CoV-2 emerged as an unknown pathogen causing a global pandemic, it exemplified the scenario that Disease X was meant to represent – an unpredictable, novel threat requiring rapid global response and adaptation

C. Aravinda

The story so far

The recent outbreak reported in the first week of December 2024 in the Democratic Republic of Congo, which has claimed over 400 lives and remains unclassified, has raised concerns that it could be an instance of Disease X. This unsettling event has reignited discussions about Disease X. Disease X is not an actual but a hypothetical disease. The World Health Organization (WHO) coined the term in 2018 to describe an unknown pathogen that could potentially unleash a devastating epidemic or pandemic. It was conceptualised by the WHO to prepare for future outbreaks that are difficult to predict or identify. While investigations continue to determine the cause in Congo, the outbreak underscores the importance of Disease X.

WHO's priority list of pathogens?

COVID-19 is widely regarded as the first instance of a real Disease X after the WHO introduced the concept in 2018. When SARS-CoV-2 emerged as an unknown pathogen causing a global pandemic, it exemplified the scenario that Disease X was meant to represent – an unpredictable, novel threat requiring rapid global response and adaptation. The concept of Disease X traces its origins in the aftermath of the West African Ebola epidemic of 2014-2016, which resulted in over 11,000 deaths and revealed significant gaps in global epidemic preparedness. After the outbreak, the WHO brought together scientists and public health experts to address how future outbreaks of similar scale could be prevented.

The WHO's priority list of pathogens is a strategic tool published in 2018 that is designed to focus global attention and resources on the most serious infectious disease threats. This list identifies diseases that have epidemic or pandemic potential for which there are insufficient or no medical countermeasures such as vaccines or treatments. The need for such a list arises from the urgency to guide research and development, allocate funding, and enhance preparedness. It helps policymakers, researchers, and health organisations prioritise efforts toward controlling the diseases. The current list (not exhaustive) includes Ebola virus disease, Marburg virus disease, Lassa fever, Nipah virus, Rift Valley fever, Crimean-Congo haemorrhagic fever, Zika virus, and Disease X. Each of these pathogens has been flagged due to factors like high mortality rates, potential for rapid spread, and the lack of adequate preventive or therapeutic options.

What is Disease X?

Disease X is not a specific illness but a placeholder for an unpredictable and



Swab samples being taken for a COVID-19 test. File THE HINDU

as-yet-undiscovered pathogen capable of sparking a global health crisis. The WHO included it in the Blueprint for Priority Diseases in 2018 to focus on the risks of emerging diseases that science has yet to encounter. The term sits at the intersection of two categories (among four) popularised by Donald Rumsfeld's matrix: "known unknowns" (threats we are aware of but cannot fully understand) and "unknown unknowns" (threats we are not aware of and understand). Disease X embodies both, as it acknowledges the likelihood of a future pandemic without specifying when, where, or how it might arise.

The potential culprits behind Disease X are varied. It originates from Pathogen X, which could be a virus, a bacterium, a parasite, fungi, helminths, or even a prion – a misfolded protein capable of causing severe neurological diseases. Historical data supports this uncertainty. Since 1940 (from where authentic records are available), researchers have identified more than 300 emerging infectious diseases, about 70% of which have zoonotic origins, meaning they are transmitted from animals to humans. This process, known as zoonotic spillover, is often linked to human encroachment on wildlife habitats, deforestation, and the intensification of agriculture. Meanwhile, the growing risks of antimicrobial resistance, bioterrorism, and accidental lab leaks add further layers of unpredictability.

Patterns in emerging diseases

While the exact nature of Disease X remains unknown, epidemiological patterns provide critical insights into how new diseases emerge and spread. The emergence of viruses such as HIV, SARS, MERS, and Ebola was closely linked to ecological disruptions caused by human activity. Deforestation, urbanisation, and climate change have pushed humans and wildlife into closer contact, increasing the

The interconnectedness of our world makes it easier for localised outbreaks to escalate into pandemics. While epidemiology cannot predict the exact moment or source of Disease X, it can help identify high-risk regions and behaviours

likelihood of pathogen transmission. Epidemiologists estimate that over 1.7 million undiscovered viruses exist in wildlife, with hundreds of thousands potentially capable of infecting humans. The frequency of novel outbreaks has also increased significantly since the mid-20th century, reflecting a combination of environmental, demographic, and global factors.

Regions with high biodiversity and inadequate healthcare systems, like the Congo Basin, are particularly vulnerable. The interconnectedness of our world, with frequent international travel and trade, makes it easier for localised outbreaks to escalate into pandemics, as seen with COVID-19. While epidemiology cannot predict the exact moment or source of Disease X, it can help identify high-risk regions and behaviours that increase the likelihood of its emergence.

Challenges of predicting Disease X

Forecasting the next Disease X is daunting, as its emergence depends on numerous unpredictable factors. Zoonotic diseases are the most likely source, given their history of driving major epidemics. However, other scenarios, such as pathogens mutating to evade treatment, laboratory mishaps, or deliberate biological attacks, cannot be ruled out. Climate change is also reshaping disease transmission dynamics, expanding the range of vector-borne illnesses like malaria and dengue fever while pushing pathogens to adapt to new

hosts and environments.

The sheer number of potential pathogens adds to the complexity. Scientists estimate that only a fraction of viruses capable of infecting humans have been identified, leaving a vast pool of unknown threats. Genomic sequencing and artificial intelligence are beginning to play an important role in narrowing this vast field of possibilities, but even with these tools, predicting the exact origin, timing, and behaviour of Disease X remains out of reach. What is certain, however, is that the conditions that gave rise to pandemics like COVID-19 and SARS continue to exist, making the emergence of Disease X a question of when, not if.

At the heart of preparation is the need for robust surveillance systems to detect new outbreaks early. Advances in genomic sequencing, artificial intelligence, and real-time data sharing are essential tools for developing diagnostics, therapeutics, and vaccines. Strengthening healthcare infrastructure, particularly in low- and middle-income countries, is also crucial. Organisations like the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) are now investing in "prototype pathogen" platforms that can be adapted to target unknown diseases within 100 days of their identification.

Need for global collaboration

Fighting Disease X will require an unprecedented level of international cooperation. The WHO's ongoing efforts, such as its list of priority pathogens and the proposed Pandemic Treaty, aim to foster a unified global response to health emergencies. These initiatives recognise that pandemics do not respect borders and that fragmented efforts will be insufficient to counter a threat as elusive as Disease X. Governments must work together to share data, pool resources, and ensure equitable access to diagnostics, treatments, and vaccines. The outbreak in the DRC serves as a sobering reminder of the risks the world faces. Disease X is no longer a distant hypothetical but an urgent call to action. By strengthening public health systems, investing in research and innovation, and fostering global solidarity, the world can prepare for the unpredictable and safeguard future generations from the devastating consequences of the next pandemic. Frameworks like the Nagoya Protocol, which ensure equitable sharing of benefits from genetic resources, could be expanded to include biological materials like pathogens. It would promote global collaboration, ensuring fair access to research and medical countermeasures during outbreaks. A novel disease anywhere is a threat to everyone.

(Dr. C. Aravinda is an academic and public health physician. The views expressed are personal. aravindaaiimsjr10@hotmail.com)

रोग X क्या है?

- परिभाषा: रोग X एक काल्पनिक शब्द है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2018 में एक अज्ञात रोगजनक को दर्शाने के लिए गढ़ा था जो संभावित रूप से वैश्विक महामारी या सर्वव्यापी महामारी का कारण बन सकता है।
- संकल्पनात्मक उत्पत्ति: यह शब्द इबोला महामारी (2014-2016) के बाद अप्रत्याशित संक्रामक रोगों के खिलाफ तैयारियों की ज़रूरत पर ज़ोर देने के लिए बनाया गया था।

➡ रोग X की प्रकृति: यह "ज्ञात अज्ञात" (ऐसे खतरे जिनके बारे में हम

जानते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं समझते हैं) और "अज्ञात अज्ञात" (ऐसे खतरे जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं) दोनों के लिए एक प्लेसहोल्डर के रूप में कार्य करता है। यह उनकी विशेषताओं को निर्दिष्ट किए बिना भविष्य की महामारियों की संभावना को स्वीकार करता है।

- ➡ संभावित रोगजनक: रोग X वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक, कृमि या प्रियन सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है। ऐतिहासिक डेटा इंगित करता है कि लगभग 70% उभरते संक्रामक रोगों की उत्पत्ति जूनोटिक है, जिसका अर्थ है कि वे जानवरों से मनुष्यों में संचारित होते हैं।
- ➡ उभरते रोग पैटर्न: नई बीमारियों का उभरना अक्सर वनों की कटाई और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले पारिस्थितिक व्यवधानों से जुड़ा होता है, जो मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच संपर्क बढ़ाते हैं।

रोग एक्स के लिए तैयार रहना क्यों महत्वपूर्ण है?

- ➡ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा: वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रोग एक्स के लिए तैयारी करना आवश्यक है। नए रोगजनकों के उभरने से व्यापक बीमारी और मृत्यु दर हो सकती है, जैसा कि COVID-19 ने प्रदर्शित किया है।
- ➡ प्रकोपों की अप्रत्याशित प्रकृति: संक्रामक रोगों के अप्रत्याशित उभरने के लिए मजबूत निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली की आवश्यकता होती है। तैयार रहने से अप्रत्याशित खतरों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।
- ➡ प्रकोपों की बढ़ती आवृत्ति: पर्यावरणीय परिवर्तनों, शहरीकरण और वन्यजीवों के आवासों पर मानव अतिक्रमण के कारण 20 वीं सदी के मध्य से नए प्रकोपों की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ➡ आर्थिक प्रभाव: महामारी के विनाशकारी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, जिससे व्यापार, यात्रा और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बाधित हो सकती है। तैयारी इन प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है।

इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? (आगे की राह)

- ➡ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति: अनुसंधान, जीनोमिक अनुक्रमण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश से उभरती बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और उनका जवाब देने की हमारी क्षमता में वृद्धि होती है।
- ➡ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: प्रकोप के प्रभावी जवाब के लिए वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण है। WHO की प्राथमिकता वाले रोगजनकों की सूची और प्रस्तावित महामारी संधि जैसी पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
- ➡ संसाधनों तक समान पहुँच: सभी देशों में निदान, उपचार और टीकों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना प्रभावी महामारी प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में।

UPSC Mains PYQ : 2020

प्रश्न: कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में अभूतपूर्व तबाही मचाई है। हालाँकि, संकट पर विजय पाने के लिए तकनीकी प्रगति का आसानी से लाभ उठाया जा रहा है। महामारी के प्रबंधन में सहायता के लिए किस प्रकार तकनीक की मदद ली गई, इसका विवरण दीजिए। (250 Words /15 marks)

2015 में, बीजिंग का वार्षिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 144 था, जो कि 2024 में दिल्ली के वर्तमान औसत 155 के बराबर है। हालाँकि, बीजिंग ने अपने प्रदूषण के स्तर में एक तिहाई की कमी हासिल की है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय गिरावट 2013 और 2017 के बीच हुई है।

Beijing's war against air pollution

Beijing in 2015 had pollution levels similar to those in Delhi today. However, through coordinated effort over several years, Beijing reduced its pollution by one-third between 2013 and 2017; by learning from Beijing's approach, Delhi can implement effective strategies to tackle its air pollution problem

EXPLAINER

Rohit Azad
Shouvik Chakraborty

Beijing, with a yearly average air quality index (AQI) of 144, was as polluted in 2015 as Delhi is today (Delhi's average is 155 for 2024). But in the interim, Beijing has managed to cut its pollution level by one-third with the most significant fall spanning between 2013 and 2017 (Chart 1). To be sure, Beijing's pollution control programme dates back to 1998 which laid the foundation for this aggressive last phase of the programme, which was termed a "war against air pollution".

Why discuss Beijing in the context of Delhi?

Beijing is the capital of an emerging economy, as is Delhi. So, if Beijing could manage what it did at its stage of development, Delhi could and needs to, as well.

There are many similarities between Beijing in 2013 and Delhi today. Chart 2 compares the sources of pollution for the two cities.

For Delhi, we have used the winter months' data because that is the most updated emission inventory available. Moreover, much like Beijing, the regional contribution to pollutants by neighbouring areas/States of the national capital region (NCR) is also high, especially during the winter months. While local emissions need to be controlled, without a concerted collective effort by the entire NCR region, just as Beijing achieved, it would be difficult to win this battle against air pollution.

What did Beijing do?

With rapid economic growth in Beijing, the ambient concentration of pollutants increased rapidly by the late 1990s. By 2017, Beijing's energy consumption had grown by 74% compared to 1998. Unfortunately, a rapid increase in urbanisation and energy consumption meant higher emissions of pollutants. Things were particularly made worse because the heating in Beijing's residential properties was heavily coal-dependent.

Beijing's 20-year anti-pollution programme can be divided into three phases – 1998-2008; 2009-12; 2013-17. One common theme that ran through the entire effort was not shock-and-awe but a careful and slowly built-up plan with people's participation, which was run autonomously by the local government of Beijing.

Sources of pollution in Beijing were broadly identified as energy structures and coal combustion (contributing 22% to PM_{2.5}), transportation structures (31%), and construction and industrial structures (33%).

For the first source, three steps were taken – ultra-low emission renovation and clean energy alternatives in power plants, renovation of coal-fired boilers, and elimination of civil bulk coal consumption used for residential heating.

For transportation infrastructure, the government first retrofitted cars and public service vehicles with diesel particulate filters (DPF) and gradually tightened emission standards. Then it went for scrapping, through subsidies instead of decree, of 'yellow-labeled' vehicles (heavy pollutant-emitting vehicles). Subway and bus infrastructure was overhauled and expanded at a rapid rate, along with optimising the urban layout.

As for the industrial and construction activities, tightening environmental requirements, intensifying end-of-pipe

Turning the tide on pollution

Beijing's battle against air pollution provides a useful framework for Delhi. With improved transportation, stricter regulations, and regional collaboration, Delhi can follow a similar path to cleaner air

Chart 1: AQI in Beijing vs Delhi 2014-24 (Yearly average)

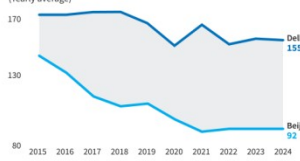
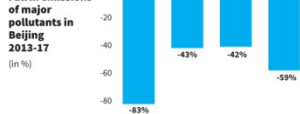


Chart 2: PM_{2.5} source apportionment for Beijing and Delhi (Beijing in 2013 and Delhi in 2023)



Chart 3: Fall in emissions of major pollutants in Beijing 2013-17 (in %)



Source: Data on Beijing has been taken from 'UN Environment 2019 - A Review of 20 Years' Air Pollution Control in Beijing', United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya, and, for Delhi, from a report titled 'Real-Time Source Apportionment and Forecasting for Advanced Air Pollution Management in Delhi' submitted to the Delhi pollution control committee

(EOP) treatment, eliminating obsolete industrial capacity, creating a green construction management model, efficient washing facilities, and implementing video monitoring with penal action against violators of construction sites were some of the steps taken.

The last leg of the plan (2013-17) especially focused on the need for regional cooperation, with five adjoining provinces around Beijing coming together to chalk out a collective plan for reducing ambient pollution in the region. This cooperation had a remarkable effect in reducing the level of pollution.

What did Beijing achieve? And how?

As a result of this meticulously planned strategy at multiple levels, sulphur dioxide, nitrogen oxide, volatile organic compounds (VOCs), and PM_{2.5}, the four major pollutants targeted under the policy, fell by 83%, 43%, 42% and 59% respectively between 2013-17 (Chart 3). Since most activities produce multiple pollutants, albeit to differing degrees, targeting a source meant reducing all the associated pollutants.

Chart 4 shows how by targeting each source, multiple pollutants were controlled.

The single most important factor in Beijing achieving its goal, apart from planning to the last detail, was the financial investment that the government committed to.

Chart 5 shows a whopping six-time jump in investment within just four years. All the steps enumerated above required heavy investment and the government did not shy away from making and fulfilling those commitments.

What can Delhi learn from the Beijing experience?

There are ideas galore on controlling pollution, and Beijing is a perfect example to learn from. We list some here, there are more.

Firstly, since private transport is the biggest contributor to local pollution, an efficient and comfortable bus-metro integrated transport system needs to be in place. Delhi's DTC bus fleet is not only old but also grossly inadequate for a population of this city's size. The metro is an excellent means of transport but is quite expensive, with almost zero last-mile connectivity provided by the State. Old vehicles need to be scrapped at the earliest through a well-thought-out subsidy-for-scrap programme, instead of banning them. Exclusive cycling and walking lanes should be built throughout the city. Other ideas, such as cross-subsidisation through affordable public transport and expensive private transport (cars and motorcycles) using congestion or high parking charges, as well as separate fuel costs for the two modes of transport, could be experimented with. An urban layout is needed where places of work and residence are brought closer, alleviating the need for long-distance travel.

Secondly, Delhi's electricity is still supplied primarily through coal-fired plants. The energy system needs a serious overhaul both from the sides of supply and demand. Subsidising solar roof tops and connecting it to the grid with electricity bill discounts could be one such step in this regard.

Thirdly, much like the Beijing plan, Delhi needs to coordinate with neighbouring regions, instead of being at

loggerheads, to control other sources which originate in these regions. Such a step may work in their collective interests.

Last but not least, the people of Delhi need to fight for the right to clean air and hold the government accountable instead of normalising poor AQIs as being better than severe ones. Prolonged exposure to pollutants, even in the poor AQI zone (for a larger part of the year), may be as dangerous as a short period of severe AQI in October and November every year. This change in attitude itself may go a long way in building pressure on the governments.

Unfortunately, it is not the lack of ideas but political will which is stopping Delhi from acting. It is the same reel playing out every year. Air in the very harmful zone for weeks with schools closing down, the young and the elderly gasping for breath through the day is the new normal in the winter months in Delhi. And what does the government do? The Centre blames the State and vice versa while they have both been in office for a decade. Neither of them is serious or even vaguely interested in solving the problem.

Schools, offices, and individuals look for solutions in the form of air purifiers, but private protection for a public bad is by definition exclusivist, with especially the disadvantaged, who contribute the least to the problem, getting a raw deal. Delhi deserves a better response. It is high time that the government, both at the Centre and the State, listened and acted.

Rohit Azad is a faculty at the Centre for Economics Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi and Shouvik Chakraborty is a Research Assistant Professor at the Political Economy Research Institute, Amherst, U.S.

THE GIST

Beijing's approach to air pollution involved a long-term, coordinated effort with a focus on regional cooperation and comprehensive policies across multiple sectors.

Key measures included improving transportation infrastructure, retrofitting vehicles, scrapping old vehicles, and enhancing industrial regulations.

Delhi can adopt similar strategies, focusing on integrated transport systems, regional collaboration, and stricter emission controls to combat its pollution crisis.



Pedestrians walk along the Kartavya Path engulfed in thick smog, near India Gate, in New Delhi, on November 18, AFP

Chart 4: Measure-specific fall in pollutants in Beijing

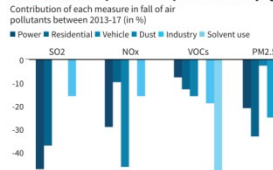
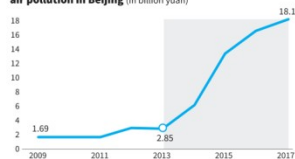


Chart 5: Financial investment to control air pollution in Beijing (in billion yuan)



दिल्ली के संदर्भ में बीजिंग की चर्चा क्यों?

- बीजिंग और दिल्ली के बीच तुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं की राजधानी हैं और वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- समान प्रदूषण स्तर: 2015 में, बीजिंग का औसत AQI 144 था, जो 2024 के लिए दिल्ली के वर्तमान औसत 155 के बराबर है। यह समानता दिल्ली में सुधार की संभावना को उजागर करती है, क्योंकि बीजिंग ने तब से अपने प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम कर दिया है।
- प्रदूषण के सामान्य स्रोत: दोनों शहरों में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, कोयले के दहन और औद्योगिक गतिविधियों सहित समान स्रोतों से उच्च प्रदूषण होता है। दोनों मामलों में वायु गुणवत्ता के मुद्दों में क्षेत्रीय योगदान भी महत्वपूर्ण है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान।
- सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता: जिस तरह बीजिंग को प्रदूषण से निपटने के लिए अपने क्षेत्र में समन्वित प्रयास की आवश्यकता है, उसी तरह दिल्ली को अपने वायु गुणवत्ता संकट को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए पड़ोसी क्षेत्रों को सामूहिक रणनीति में शामिल करना चाहिए।

बीजिंग ने क्या किया और उसने इसे कैसे हासिल किया?

- चरणबद्ध और रणनीतिक योजना: स्थानीय सरकार की स्वायत्तता और जन भागीदारी के साथ तीन चरणों (1998-2017) में 20 वर्षीय प्रदूषण विरोधी कार्यक्रम को लागू किया गया, ताकि क्रमिक और सतत प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
 - 1998-2008: प्रारंभिक आधारभूत कार्य।
 - 2009-2012: विनियमन को मजबूत करना।
 - 2013-2017: आक्रामक उपायों को "वायु प्रदूषण के खिलाफ युद्ध" कहा गया।
- ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव: बिजली संयंत्रों का नवीनीकरण करके, कोयला बॉयलरों को हटाकर और आवासीय कोयला हीटिंग को बदलकर कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरित किया गया, जिससे प्रमुख उत्सर्जन में कमी आई।
- परिवहन सुधार: सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को उन्नत किया गया, वाहनों में उत्सर्जन नियंत्रण शुरू किया गया और सब्सिडी के साथ प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया, जिससे परिवहन-आधारित प्रदूषकों में कमी आई।
- क्षेत्रीय सहयोग और निवेश: समन्वित प्रदूषण नियंत्रण के लिए पांच पड़ोसी प्रांतों के साथ भागीदारी की गई और लक्षित उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्तीय निवेश में छह गुना वृद्धि की गई।
- वित्तीय निवेश: चार वर्षों में निवेश में छह गुना वृद्धि ने इन पहलों का समर्थन किया, जिससे महत्वपूर्ण अवसंरचना सुधार और नियामक प्रवर्तन संभव हुआ।
- इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, सल्फर डाइऑक्साइड और PM2.5 जैसे प्रमुख प्रदूषकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई (उदाहरण के लिए, 2013-2017 के बीच PM2.5 में 59% की कमी आई)।

बीजिंग के अनुभव से दिल्ली क्या सीख सकती है?

- एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली: निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए एक कुशल बस-मेट्रो प्रणाली की स्थापना आवश्यक है। बस बेड़े को अपग्रेड करना और अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाना सार्वजनिक परिवहन पहुंच में काफी सुधार कर सकता है।
- ऊर्जा संक्रमण: बीजिंग के कोयले से दूर जाने के समान, दिल्ली को कोयले से चलने वाले संयंत्रों पर निर्भरता कम करते हुए सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देकर अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी चाहिए।
- क्षेत्रीय समन्वय: प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को शहर की सीमाओं से आगे बढ़ाकर पड़ोसी क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए, जिससे बीजिंग की क्षेत्रीय पहलों के समान सहयोग को बढ़ावा मिले।
- स्वच्छ वायु के लिए सार्वजनिक वकालत: सरकार से जवाबदेही की मांग करने में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण कर सकता है।

► राजनीतिक इच्छाशक्ति और स्थिरता: वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक कार्य योजना की आवश्यकता होती है, न कि ऐसे तदर्थ उपायों की जो मूल कारणों से निपटने में विफल होते हैं।

आगे की राह:

- नीति कार्यान्वयन और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना: क्षेत्रीय प्रदूषण स्रोतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों को शामिल करते हुए समन्वित प्रयासों के साथ एक व्यापक, दीर्घकालिक प्रदूषण नियंत्रण नीति तैयार करना और उसे लागू करना।
- स्थायी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना: जवाबदेही और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ हवा के लिए सार्वजनिक भागीदारी और वकालत को बढ़ावा देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, हरित सार्वजनिक परिवहन और शहरी नियोजन में निवेश करना।

UPSC Mains PYQ : 2015

प्रश्न: मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन बड़े शहर हैं, लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या अन्य दो शहरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। ऐसा क्यों है?



In News : Willow Chip

हाल ही में, गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है, जब उसने 'विलो' नामक अपनी अगली पीढ़ी की चिप का अनावरण किया।



विलो चिप के बारे में:

- यह Google द्वारा विकसित एक नई अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है।
- चिप के घटकों में सिंगल और टू-क्यूबिट गेट, क्यूबिट रीसेट और रीडआउट शामिल हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर और एकीकृत किया गया है कि किसी भी दो घटकों के बीच कोई अंतराल न हो क्योंकि इससे सिस्टम के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- यह केवल पाँच मिनट में एक जटिल गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम था - एक ऐसा कार्य जो शास्त्रीय कंप्यूटरों को ब्रह्मांड के इतिहास से भी अधिक समय लेगा।
- इसने पाँच मिनट से कम समय में एक मानक बेंचमार्क गणना की, जो आज के सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटरों में से एक को 10 सेटिलियन (यानी, 1025) साल लगेगे।
- यह सुपरकंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट का उपयोग करके संचालित होता है - बहुत कम तापमान पर क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करने वाले छोटे विद्युत सर्किट। इन सर्किटों को क्वांटम अवस्था में कृत्रिम परमाणुओं की तरह काम करने के लिए इंजीनियर किया गया है।

क्वांटम चिप क्या है?

- क्वांटम चिप एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर चिप है जिसे क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो परमाणुओं जैसे बहुत छोटे कणों का विज्ञान है।
- -जबकि नियमित चिप्स सूचना को संसाधित करने के लिए 'बिट्स' (0 या 1) का उपयोग करते हैं, क्वांटम चिप्स 'क्यूबिट्स' का उपयोग करते हैं, जो एक ही समय में 0 या 1 या दोनों हो सकते हैं।
- यह अनूठी क्षमता क्वांटम चिप्स को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में जटिल गणनाओं को बहुत तेज़ी से संभालने की अनुमति देती है।

Page : 08 Editorial Analysis

The missing spotlight on urban local government polls

Urban local governments (ULGs) function as units of decentralised local self-governance, and are responsible for delivering civic services at the first mile, ensuring quality of life for citizens. The 74th Constitutional Amendment Act (CAA) was introduced in 1992 to codify this role of ULGs. Over 30 years later, the objectives of this landmark amendment are yet to be realised. The ongoing discourse on simultaneous elections, popularly known as One Nation One Election (ONOE), is a unique opportunity to spotlight a basic requirement of local democracy, i.e., elections to ULGs – a consideration that has generally been absent in deliberations on the ONOE.

'State subjects' as reasoning

The 79th report of the Parliament Standing Committee on Law and Justice on the 'Feasibility of Simultaneous Elections,' submitted in 2015, while advocating simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assemblies, was silent on elections to ULGs. A discussion paper (2017) by the NITI Aayog, on 'Analysis of Simultaneous Elections', kept ULGs out of its purview, arguing that the third-tier institutions are State subjects and that the sheer number of such institutions across the country makes it "impractical, and possibly impossible, to synchronise elections". Similar reasoning is put forward in the 2018 draft report of the Law Commission of India on simultaneous elections. But in a refreshing departure, the High Level Committee (HLC) constituted by the Government of India to provide a road map for implementation of simultaneous elections, deliberated on local body elections and recommended synchronising them within 100 days of simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assemblies.

India has over 4,800 ULGs that oversee nearly 40% of the population, a figure which is estimated to cross 50% by 2050. Cities are the backbone of the country's economy, contributing over 60% to India's GDP. Well-governed cities



Santosh Nargund

Head, Participatory Governance at the Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy



Maansi Verma

Manager, Policy Engagement at the Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy

The ongoing discourse on simultaneous elections, or ONOE, is the right opportunity for change

accelerate economic growth, and promote social and cultural well being. Thus, ensuring regular elections to install democratically-elected governments in our cities every five years ought to be a matter of mainstream political discourse and policy formulation. The HLC report, which was accepted by the Union government in September 2024, touched upon the procedure of elections to local governments and is a good start in this direction. However, deeper analysis is necessary to understand and address the current state of affairs of elections to ULGs.

Uncertainty and delays in elections

It may come as a surprise to many that despite the constitutional mandate of holding elections to municipalities every five years, elections are routinely delayed across thousands of ULGs – sometimes by several years. According to the Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 (published by the Comptroller and Auditor General, or CAG of India in November 2024), elections were delayed in over 60% of ULGs across India. Such ULGs are directly governed by State governments, violating the principle of decentralisation as envisaged in the Constitution. This also adversely impacts accountability as citizens lack representation and have limited avenues for airing their grievances and development needs. Elections that are held on time are the *sine qua non* for democracy – not just for Parliament and the State legislatures but also for every municipality in the country.

Holding elections to ULGs is not enough. After the results are announced, the elected councils have to be operationalised with State governments calling for their first meeting to enable elections to the offices of mayors/chairpersons and standing committees. A study undertaken by Janaagraha found that there was a delay by 11 months on average in the formation of councils after the declaration of election results of the municipal corporations in

Karnataka. In effect, ULGs continue to function under the administrative control of State governments. This defeats the electoral mandate given by the people, making elected city councillors powerless to attend to the development needs of their electorate.

Disempowered State Election Commissions

Another important issue is the disempowerment of the State Election Commissions (SECs), which are constitutional bodies responsible for supervising and conducting ULG elections. The CAG report notes that only four out of the 15 States assessed have empowered their SECs to carry out ward delimitation. The report further notes that elections to ULGs were delayed due to a delay in ward delimitation by State governments or because of court cases regarding reservations. Given the high political ramifications of ward delimitation and reservation exercises, it is necessary that these functions are carried out by independent authorities such as the SECs.

A holistic analysis of the challenges in conducting elections to ULGs promptly is important in the ongoing national discourse on the synchronisation of elections. There is an urgent need to build on the beginning made by the HLC to effect the reforms necessary in ULG elections.

The Government of India has proposed setting up an implementation group to prepare a plan of action that would execute the HLC's recommendations. The government has also expressed its intent to have consultations across the country on this topic. It is hoped and expected that the agenda for reforms to ensure regular and scheduled elections to ULGs will feature in these dialogues and that the Union and State governments will come together to make local democracy in our cities operational and vibrant.

The views expressed are personal

GS Paper 02 : भारतीय राजनीति

PYQ : (UPSC CSE (M) GS-2 2020) भारत में स्थानीय संस्थाओं की ताकत और संधारण उनके 'कार्य, कार्यकर्ता और निधि' के प्रारंभिक चरण से 'कार्यक्षमता' के समकालीन चरण में स्थानांतरित हो गया है। हाल के समय में स्थानीय संस्थाओं द्वारा उनकी कार्यक्षमता के संदर्भ में सामना की जाने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डालें। (250 Words /15 marks)

UPSC Mains Practice Question: शहरी स्थानीय निकाय चुनाव भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की आधारशिला हैं। शहरी शासन को मजबूत करने में उनकी भूमिका और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। (250 words, 15 marks)

संदर्भ:

- एक साथ चुनाव कराने पर चल रही बहस, जिसे आमतौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE) के रूप में जाना जाता है, स्थानीय लोकतंत्र के एक बुनियादी पहलू को उजागर करने का एक मूल्यवान अवसर प्रस्तुत करता है: शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) के लिए चुनाव की आवश्यकता।
- शहरी स्थानीय सरकार के चुनावों का क्या महत्व है?
- विकेंद्रीकृत शासन: ULG विकेंद्रीकृत स्वशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक कामकाज के लिए मौलिक है।
- सेवा वितरण: ULG पानी, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी नियोजन जैसी आवश्यक नागरिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती हैं।
- स्थानीय लोकतंत्र: ULG के नियमित चुनाव लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित करते हैं, जिससे नागरिक स्थानीय स्तर पर शासन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और स्थानीय प्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सकते हैं।
- आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: ULG शहरी विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि शहर देश के सकल घरेलू उत्पाद के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए अच्छी तरह से शासित स्थानीय निकाय राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान करते हैं।
- शहरी स्थानीय चुनावों में मतदाता मतदान आम तौर पर कम क्यों होता है? जागरूकता की कमी: स्थानीय चुनावों के बारे में मतदाता जागरूकता अक्सर राज्य या राष्ट्रीय चुनावों की तुलना में कम होती है, जिससे भागीदारी कम होती है। माना जाने वाला प्रभाव: कई मतदाताओं को लगता है कि शहरी स्थानीय चुनावों का प्रभाव राज्य या राष्ट्रीय चुनावों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता उदासीन हो जाते हैं। राजनीतिक अलगाव: कई मामलों में, शहरी निवासी स्थानीय शासन से अलग-थलग महसूस कर सकते हैं, खासकर जब स्थानीय मुद्दों को तत्काल नहीं माना जाता है या जब राजनीतिक अभियान उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं। समय और शेड्यूलिंग मुद्दे: यूएलजी के चुनाव अलग-अलग समय पर हो सकते हैं या अन्य चुनावों के साथ समन्वयित नहीं हो सकते हैं, जिससे भ्रम और अलगाव हो सकता है। मतदाता थकान: विभिन्न स्तरों पर लगातार चुनाव मतदाता थकान में योगदान दे सकते हैं, जिससे स्थानीय चुनावों में भागीदारी दर कम हो सकती है। शहरी स्थानीय सरकारों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं? राज्य चुनाव आयोगों (एसईसी) को सशक्त बनाना: समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उन्हें स्वायत्तता और संसाधन देकर एसईसी को मजबूत करना आवश्यक है। वर्तमान में, कई एसईसी के पास वार्ड परिसीमन को प्रभावी ढंग से करने का अधिकार नहीं है, जिससे चुनाव में देरी होती है। नियमित चुनाव: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यूएलजी हर पांच साल में नियमित चुनाव आयोजित करें। स्थानीय निकाय चुनावों को राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के साथ समन्वयित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशों को स्वीकार

करना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण: 74 वें संविधान संशोधन का उद्देश्य यूएलजी को शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना था; हालाँकि, वास्तविक कार्यान्वयन असंगत रहा है। सार्वजनिक भागीदारी: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से यूएलजी के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसे सामुदायिक जुड़ाव पहल और भागीदारी बजट प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आगे का रास्ता: संस्थागत क्षमता और स्वायत्तता को मजबूत करना: समय पर और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोगों (एसईसी) को आवश्यक अधिकार और संसाधनों से सशक्त बनाना। सार्वजनिक जुड़ाव और जवाबदेही को बढ़ावा देना: सामुदायिक जुड़ाव, भागीदारी बजट और शासन में पारदर्शिता जैसी पहलों के माध्यम से सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इससे नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति यूएलजी की प्रतिक्रिया में सुधार आएगा तथा स्थानीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।

